

डिजिटल भुगतान और UPI का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

डॉ. रमेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

रामबचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय बगली पिजड़ा मऊ।

Email: kanakprakashan@gmail.com



Received 01 September 2026

Accepted 05 September 2026

Published 06 September 2026

Corresponding Author:

डॉ रमेश कुमार

Email: kanakprakashan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64880/pcjaict.v1i5.01>

Funding: This research received no specifics grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

सारांश :

भारत में पिछले एक दशक के दौरान डिजिटल भुगतान व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। विशेष रूप से यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात् UPI ने भुगतान की पारंपरिक व्यवस्था को सरल, त्वरित और कम लागत वाला बनाकर आर्थिक लेन-देन की प्रकृति बदल दी है। इसका प्रभाव अब केवल महानगरों और औपचारिक व्यवसायों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण बाजारों, छोटे दुकानदारों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म उद्यमियों और सामान्य ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुका है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में UPI के माध्यम से लगभग 241.62 अरब लेन-देन हुए, जिनका कुल मूल्य लगभग ₹314.2 लाख करोड़ रहा। इसी अवधि में कुल खुदरा भुगतान लेन-देन की संख्या में UPI की हिस्सेदारी लगभग 86 प्रतिशत थी। जून 2026 में अकेले UPI के माध्यम से लगभग 22.72 अरब लेन-देन हुए, जिनका मूल्य ₹28.92 लाख करोड़ से अधिक रहा।

ग्रामीण भारत में डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकृति के पीछे जन-धन खातों, आधार, मोबाइल फोन, बैंकिंग प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और QR आधारित भुगतान व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। 19 अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत कुल 59.09 करोड़ लाभार्थियों में लगभग 45.95 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी बैंकिंग केंद्रों से संबंधित थे। इससे स्पष्ट है कि भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन का आधार तेजी से विस्तृत हुआ है।

प्रस्तुत शोध आलेख द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वित्त मंत्रालय, DBT भारत, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के आँकड़ों एवं अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि UPI और डिजिटल भुगतान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लेन-देन लागत घटाने, वित्तीय समावेशन बढ़ाने, सरकारी सहायता की पारदर्शिता सुधारने, छोटे व्यवसायों के विस्तार, ग्रामीण परिवारों की आर्थिक सुरक्षा तथा औपचारिक ऋण तक पहुँच में सकारात्मक योगदान दिया है। फिर भी डिजिटल साक्षरता, साइबर धोखाधड़ी, कमजोर इंटरनेट संपर्क, लैंगिक डिजिटल अंतर और शिकायत निवारण जैसी चुनौतियाँ इसके समावेशी विस्तार के लिए गंभीर विषय बनी हुई हैं।

प्रमुख शब्द: डिजिटल भुगतान, UPI, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल बैंकिंग, ग्रामीण उद्यमिता।

1. प्रस्तावना: भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था लंबे समय तक नकद आधारित रही है। गाँवों में कृषि उपज की खरीद-बिक्री, मजदूरी, स्थानीय दुकानों से सामान की खरीद, छोटे ऋण, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और घरेलू आवश्यकताओं से जुड़े अधिकांश लेन-देन नकद में किए जाते रहे हैं। बैंक शाखाओं की

दूरी, परिवहन लागत, सीमित बैंकिंग समय तथा दस्तावेजी प्रक्रियाओं के कारण ग्रामीण लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का नियमित उपयोग अपेक्षाकृत कठिन था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार, आधार व्यवस्था, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सस्ते मोबाइल इंटरनेट, स्मार्टफोन तथा डिजिटल भुगतान प्रणालियों के विकास ने इस स्थिति में परिवर्तन किया। वर्ष 2016 में UPI की शुरुआत इस परिवर्तन का एक निर्णायक चरण सिद्ध हुई। UPI ने अलग-अलग बैंकों के खाताधारकों को मोबाइल के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। QR कोड ने छोटी दुकानों और सूक्ष्म व्यापारियों के लिए अलग-अलग महंगी भुगतान मशीनों की आवश्यकता को भी काफी हद तक समाप्त कर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI को भारत में व्यक्ति-से-व्यक्ति और व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम माना है। RBI के अनुसार UPI लेन-देन की मात्रा 2018-19 के 539 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 13,113 करोड़ हो गई थी और इसी अवधि में इसके माध्यम से किए गए भुगतान का मूल्य ₹8.8 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग ₹200 लाख करोड़ हो गया। इसके बाद भी वृद्धि जारी रही और 2025-26 में UPI लेन-देन लगभग 24,161.69 करोड़ तक पहुँच गए। इस विस्तार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत की बड़ी जनसंख्या गाँवों और छोटे कस्बों में निवास करती है। डिजिटल भुगतान यदि केवल भुगतान की तकनीक न रहकर बचत, ऋण, सरकारी सहायता, बाजार तक पहुँच तथा सूक्ष्म उद्यमिता को प्रभावित करता है, तो इसका प्रभाव ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान तथा UPI के विस्तार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव समझना है। विशेष रूप से अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि डिजिटल भुगतान ने ग्रामीण वित्तीय समावेशन, छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार, किसानों एवं ग्रामीण परिवारों की आर्थिक गतिविधियों, सरकारी लाभ हस्तांतरण, औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक पहुँच और ग्रामीण बाजारों की कार्यकुशलता को किस प्रकार प्रभावित किया है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान के विस्तार में उपस्थित डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और तकनीकी बाधाओं की भी समीक्षा की गई है।

3. शोध-पद्धति

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टें एवं शोध प्रकाशनों, National Payments Corporation of India के UPI आँकड़ों, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के आधिकारिक पोर्टल, भारत सरकार के Direct Benefit Transfer पोर्टल, World Bank Global Findex, IMF Working Papers तथा Bank for International Settlements के शोध-पत्रों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन में राष्ट्रीय स्तर के कुल आँकड़ों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ते समय सावधानी बरती गई है। केवल UPI लेन-देन बढ़ने को ग्रामीण आय में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना गया है। जहाँ आर्थिक प्रभाव के संबंध में कारणात्मक या निकट-कारणात्मक निष्कर्ष दिए गए हैं, वहाँ उपलब्ध अनुभवजन्य शोध अध्ययनों का सहारा लिया गया है।

4. भारत में डिजिटल भुगतान और UPI का विस्तार

भारतीय भुगतान प्रणाली के तेजी से डिजिटलीकरण को RBI के Digital Payments Index से भी समझा जा सकता है। मार्च 2018 को आधार वर्ष मानकर इस सूचकांक का मूल्य 100 निर्धारित किया गया था। मार्च 2024 में यह 445.50 और मार्च 2025 में 493.22 तक पहुँच गया। इससे भुगतान अवसंरचना, उपभोक्ता स्वीकार्यता और डिजिटल भुगतान प्रदर्शन में व्यापक वृद्धि का संकेत मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में UPI के माध्यम से लगभग 2,41,616.9 मिलियन अर्थात् 241.62 अरब लेन-देन हुए और उनका मूल्य लगभग ₹314.2 लाख करोड़ रहा। एक वर्ष पहले 2024-25 में UPI लेन-देन की संख्या लगभग 185.87 अरब तथा मूल्य ₹260.6 लाख करोड़ था। RBI के अनुसार

2025-26 में UPI की लेन-देन मात्रा में लगभग 30 प्रतिशत और मूल्य में 20.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी वर्ष UPI का कुल खुदरा भुगतान लेन-देन की मात्रा में योगदान लगभग 86 प्रतिशत था।

NPCI के आँकड़े भी इस वृद्धि की निरंतरता दर्शाते हैं। जून 2026 में लगभग 22.72 अरब UPI लेन-देन हुए जिनका मूल्य लगभग ₹28.92 लाख करोड़ था। यह वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि UPI में बहुत छोटी राशि का भुगतान भी संभव है। कोई ग्रामीण उपभोक्ता किराना दुकान, सब्जी विक्रेता, दवा विक्रेता, खाद-बीज की दुकान या स्थानीय सेवा प्रदाता को कुछ रुपये से लेकर बड़ी राशि तक तत्काल भुगतान कर सकता है। इससे डिजिटल भुगतान का उपयोग बड़े आर्थिक लेन-देन तक सीमित न रहकर दैनिक ग्रामीण जीवन का हिस्सा बनने की क्षमता रखता है।

5. जन-धन योजना और ग्रामीण डिजिटल भुगतान का आधार

डिजिटल भुगतान के लिए बैंक खाता पहली बुनियादी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आधार तैयार किया। 19 अगस्त 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 59.09 करोड़ लाभार्थी थे। इनमें 45.95 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी बैंक शाखा केंद्रों से संबंधित थे, अर्थात् कुल जन-धन खाताधारकों का लगभग 78 प्रतिशत। कुल लाभार्थियों में लगभग 32.92 करोड़ महिलाएँ थीं। खातों में कुल जमा राशि ₹3.16 लाख करोड़ से अधिक थी और लगभग 41.29 करोड़ RuPay कार्ड जारी किए जा चुके थे।

इस संरचना ने ग्रामीण परिवारों को बैंक खाता, सरकारी सहायता, बचत और डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। बैंक खाता उपलब्ध होने पर वही व्यक्ति UPI, मोबाइल बैंकिंग, आधार आधारित भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर सकता है। विश्व बैंक के Global Findex 2021 के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 78 प्रतिशत वयस्कों के पास वित्तीय खाता था, जबकि 2011 में यह अनुपात लगभग 35 प्रतिशत था। यह वृद्धि वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देती है।

6. ग्रामीण छोटे व्यापार और सूक्ष्म उद्यमिता पर प्रभाव

UPI का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव गाँवों और छोटे कस्बों के छोटे व्यापारियों पर दिखाई देता है। पारंपरिक कार्ड भुगतान प्रणाली में व्यापारी को भुगतान मशीन, नेटवर्क और विभिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती थी। QR आधारित UPI भुगतान ने प्रवेश लागत कम कर दी। आज छोटा किराना दुकानदार, चाय विक्रेता, सब्जी विक्रेता, स्थानीय कारीगर या सेवा प्रदाता भी QR कोड के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर सकता है।

इससे व्यवसाय का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होता है। नकद व्यापार में छोटे व्यापारी की वास्तविक बिक्री का दस्तावेजी प्रमाण सीमित रहता था। डिजिटल लेन-देन के माध्यम से नियमित आय और नकदी प्रवाह का रिकॉर्ड बनने पर भविष्य में औपचारिक ऋण मूल्यांकन में सहायता मिल सकती है। Dubey और Purnanandam के भारत-आधारित अध्ययन में पाया गया कि जिन जिलों में डिजिटल भुगतान का विस्तार अधिक हुआ, वहाँ UPI की शुरुआत के बाद घरेलू आय और छोटे व्यवसायों की गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए। इसका प्रभाव विशेष रूप से स्वरोजगार करने वाले कमजोर आर्थिक वर्गों, जैसे छोटे व्यापारी और फेरीवालों, पर अधिक पाया गया। अध्ययन ने ऋण संबंधी बाधाओं में कमी और लेन-देन लागत में कमी को प्रमुख माध्यम बताया। इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक अर्थ है। डिजिटल भुगतान छोटे व्यापारी को केवल नकद उपलब्धता वाले ग्राहकों पर निर्भर नहीं रहने देता। ग्राहक के पास नकद न होने पर भी खरीद संभव हो जाती है। इससे बिक्री के अवसर बढ़ सकते हैं और स्थानीय बाजार में धन का प्रवाह अधिक सुचारु हो सकता है।

7. किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए उपयोगिता

ग्रामीण परिवारों के लिए डिजिटल भुगतान का प्रभाव केवल बाजार में भुगतान करने तक सीमित नहीं है। किसी परिवार का सदस्य शहर या दूसरे राज्य में कार्यरत है तो वह कुछ ही सेकंड में गाँव स्थित परिवार को पैसा भेज सकता है। आपातकालीन चिकित्सा, कृषि इनपुट, शिक्षा शुल्क या घरेलू आवश्यकता के समय इस प्रकार का तत्काल हस्तांतरण विशेष रूप से उपयोगी है।

IMF के Patnam और Yao के भारत संबंधी अध्ययन में मोबाइल धन के बड़े डेटा सेट का विश्लेषण किया गया। शोध में पाया गया कि डिजिटल धन हस्तांतरण ने वर्षा संबंधी आर्थिक झटकों के दौरान परिवारों की आर्थिक सहनशीलता बढ़ाने में योगदान दिया। अधिक मोबाइल मनी उपयोग वाले क्षेत्रों में प्रतिकूल वर्षा झटकों का आर्थिक गतिविधियों और उपभोग पर प्रभाव अपेक्षाकृत कम पाया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यह निष्कर्ष विशेष महत्व रखता है क्योंकि कृषि आय मौसम, मानसून, फसल मूल्य और स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तत्काल डिजिटल धन हस्तांतरण परिवार और सामाजिक नेटवर्क के बीच अनौपचारिक आर्थिक सहायता को अधिक तेज और सुविधाजनक बना सकता है।

8. सरकारी योजनाएँ, DBT और ग्रामीण कल्याण

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकारी योजनाओं की बड़ी भूमिका है। किसान सहायता, मनरेगा मजदूरी, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और विभिन्न सब्सिडियों का भुगतान डिजिटल माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में किए जाने से बिचौलियों और भुगतान विलंब को कम करने की क्षमता पैदा हुई है।

भारत सरकार के DBT पोर्टल पर अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में कुल संचयी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ₹53 लाख करोड़ से अधिक प्रदर्शित किया जा रहा था। DBT तथा संबंधित प्रशासनिक सुधारों से मार्च 2025 तक अनुमानित लाभ या बचत लगभग ₹5.14 लाख करोड़ बताई गई है। सरकार के अनुसार यह लाभ मुख्यतः अपात्र, डुप्लिकेट अथवा अस्तित्वहीन लाभार्थियों को हटाने तथा रिसाव कम करने से संबंधित है।

RBI भी मानता है कि आधार भुगतान ब्रिज और डिजिटल भुगतान ने दूरदराज क्षेत्रों में सरकारी सब्सिडी, मजदूरी और अन्य लाभ सीधे खातों में भेजने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और कुशल बनाया है। हालाँकि DBT और UPI समान व्यवस्था नहीं हैं, पर दोनों एक-दूसरे को पूरक बनाते हैं। बैंक खाते में सरकारी राशि प्राप्त होने के बाद लाभार्थी UPI या अन्य डिजिटल माध्यम से उसी धन का उपयोग कर सकता है। इससे खाते का उपयोग केवल सरकारी भुगतान प्राप्त करने तक सीमित न रहकर सक्रिय आर्थिक लेन-देन में बदल सकता है।

9. वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता में सुधार

वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल बैंक खाता खोलना नहीं है। वास्तविक समावेशन तब होता है जब व्यक्ति खाते का उपयोग भुगतान, बचत, ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए नियमित रूप से करे। RBI का Financial Inclusion Index मार्च 2024 के 64.2 से बढ़कर मार्च 2025 में 67.0 हो गया। RBI के अनुसार इसमें उपयोग और गुणवत्ता संबंधी आयामों में सुधार की विशेष भूमिका रही।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2025 तक RBI के आँकड़ों में लगभग 7.57 लाख निश्चित बैंकिंग प्रतिनिधि केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बताए गए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग प्रतिनिधि लेन-देन में ग्रामीण हिस्सेदारी भी उल्लेखनीय थी।

इस प्रकार डिजिटल भुगतान को केवल मोबाइल ऐप के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। बैंकिंग प्रतिनिधि, जन-धन खाता, आधार आधारित प्रणाली और मोबाइल भुगतान एक संयुक्त वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं।

10. ग्रामीण महिलाओं पर संभावित प्रभाव

ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में डिजिटल वित्त का विशेष सामाजिक-आर्थिक महत्व है। यदि सरकारी सहायता या आजीविका से प्राप्त आय महिला के व्यक्तिगत बैंक खाते में आती है और वह मोबाइल के माध्यम से उसके उपयोग पर अधिक नियंत्रण रखती है, तो परिवार में उसकी आर्थिक निर्णय क्षमता मजबूत हो सकती है। जन-धन योजना के अगस्त 2026 के आँकड़ों में लगभग 32.92 करोड़ महिला लाभार्थी दर्ज थे। यह वित्तीय समावेशन के लिए मजबूत आधार है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ डिजिटल भुगतान के माध्यम से बचत, आपसी लेन-देन और सूक्ष्म उद्यमों के भुगतान को अधिक व्यवस्थित कर सकती हैं। फिर भी खाता स्वामित्व और डिजिटल उपयोग में अंतर समझना आवश्यक है। विश्व बैंक के Global Findex 2021 में भारत में पुरुषों और

महिलाओं के बैंक खाता स्वामित्व का अंतर बहुत कम पाया गया, लेकिन डिजिटल भुगतान के उपयोग में लैंगिक अंतर बना हुआ था। अतः केवल महिलाओं के नाम खाते खोलना पर्याप्त नहीं है; मोबाइल स्वामित्व, डिजिटल साक्षरता और स्वतंत्र उपयोग क्षमता भी आवश्यक है।

11. स्थानीय बाजारों की कार्यकुशलता और पारदर्शिता

नकद आधारित व्यवस्था में छुट्टे पैसे की समस्या, नकदी सुरक्षित रखने का जोखिम और दिन के अंत में नकदी जमा करने की आवश्यकता रहती है। डिजिटल भुगतान इन लागतों को कम कर सकता है। व्यापारी तुरंत देख सकता है कि भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं और ग्राहक को भी भुगतान का डिजिटल प्रमाण मिलता है। डिजिटल लेन-देन छोटे व्यवसायों के लिए हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने में भी सहायता कर सकता है। व्यापार का डिजिटल इतिहास उपलब्ध होने से आय, बिक्री और नकदी प्रवाह का बेहतर अनुमान संभव है।

BIS के Aguilar, Frost, Guerra, Kamin और Tombini के 101 अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित अध्ययन में डिजिटल भुगतान उपयोग में एक प्रतिशत-बिंदु वृद्धि को दो वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि में लगभग 0.10 प्रतिशत-बिंदु वृद्धि तथा अनौपचारिक रोजगार के हिस्से में लगभग 0.06 प्रतिशत-बिंदु कमी से संबंधित पाया गया। शोध में डिजिटल भुगतान और औपचारिक ऋण तक बेहतर पहुँच के बीच भी सकारात्मक संबंध मिला।

यद्यपि यह वैश्विक अध्ययन है और इसके परिणाम सीधे प्रत्येक भारतीय गाँव पर लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी यह संकेत देता है कि भुगतान के डिजिटलीकरण का व्यापक आर्थिक औपचारिकीकरण और वित्तीय पहुँच से संबंध हो सकता है।

12. कम इंटरनेट वाले क्षेत्रों के लिए नई तकनीकें

ग्रामीण डिजिटल भुगतान की सबसे बड़ी समस्याओं में इंटरनेट और स्मार्टफोन की उपलब्धता रही है। इस बाधा को कम करने के लिए UPI प्रणाली में विशेष सुविधाएँ विकसित की गई हैं।

UPI 123PAY फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को भी डिजिटल भुगतान की सुविधा देने के लिए बनाया गया है। NPCI के अनुसार यह व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्रों तक भुगतान सेवाओं की पहुँच बढ़ाने तथा कम या बिना इंटरनेट संपर्क वाली स्थितियों में व्यापारियों को भुगतान प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। इसी प्रकार UPI Lite कम मूल्य के भुगतान को अधिक सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। NPCI के अनुसार UPI Lite ₹1,000 से कम मूल्य के लेन-देन को PIN रहित तरीके से संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है। क्षेत्रीय भाषाओं और आवाज आधारित तकनीक का विकास भी ग्रामीण और कम डिजिटल साक्षर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकता है। NPCI का Hello! UPI क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद आधारित भुगतान और फीचर फोन सहित विभिन्न उपकरणों पर उपलब्धता को प्रोत्साहित करता है।

13. डिजिटल भुगतान और ऋण की उपलब्धता

ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यापारियों की एक प्रमुख समस्या औपचारिक ऋण प्राप्त करना है। कई व्यवसायों के पास नियमित लेखा-विवरण, वेतन रिकॉर्ड या औपचारिक बिक्री दस्तावेज नहीं होते। इसके कारण बैंक उनकी वास्तविक आय और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन कठिन मान सकते हैं। डिजिटल भुगतान इस सूचना-अंतर को कम कर सकता है। नियमित UPI भुगतान का रिकॉर्ड व्यापार की गतिविधि, बिक्री की आवृत्ति और नकदी प्रवाह का एक संकेत प्रदान कर सकता है। RBI ने भी माना है कि डिजिटल भुगतान से उत्पन्न वास्तविक समय के व्यापारिक आँकड़े छोटे व्यवसायों के ऋण मूल्यांकन में उपयोगी हो सकते हैं। हालाँकि यहाँ सावधानी आवश्यक है। डिजिटल लेन-देन डेटा के आधार पर ऋण प्रदान करते समय उपभोक्ता की सहमति, डेटा गोपनीयता, उचित ब्याज दर तथा पारदर्शी एल्गोरिदमिक मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए। अन्यथा वित्तीय समावेशन के नाम पर अत्यधिक ऋण या अनुचित डिजिटल ऋण का जोखिम पैदा हो सकता है।

14. प्रमुख चुनौतियाँ: UPI का विस्तार प्रभावशाली है, पर ग्रामीण भारत में पूर्ण डिजिटल समावेशन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। RBI के 2022 के लगभग 90,000 प्रतिभागियों वाले सर्वेक्षण में उपभोक्ताओं और व्यापारियों में डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूकता काफी अधिक पाई गई, लेकिन जागरूकता

और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर था। केवल 41.9 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने किसी डिजिटल भुगतान माध्यम का कभी उपयोग किया था और लगभग 36.1 प्रतिशत वर्तमान उपयोगकर्ता थे। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उपयोग महानगरीय क्षेत्रों से कम था।

डिजिटल विभाजन दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है। RBI ने अप्रैल 2024 के आँकड़ों के आधार पर उल्लेख किया था कि प्रति 100 जनसंख्या इंटरनेट सदस्यता ग्रामीण भारत में लगभग 44.2 थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 111.8 थी। अर्थात् भुगतान तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद कनेक्टिविटी समान रूप से उपलब्ध नहीं है।

तीसरी चुनौती साइबर धोखाधड़ी है। ग्रामीण या नए डिजिटल उपयोगकर्ताओं को नकली ग्राहक सेवा नंबर, फिशिंग लिंक, QR कोड धोखाधड़ी, OTP अथवा UPI PIN साझा करवाने, स्क्रीन-शेयरिंग ऐप और सामाजिक अभियांत्रिकी जैसी धोखाधड़ियों का अधिक खतरा हो सकता है। RBI ने भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था में फिशिंग, मैलवेयर और अन्य साइबर जोखिमों को उपभोक्ता विश्वास के लिए गंभीर चुनौती माना है। नेटवर्क विफलता और भुगतान लंबित रहने की समस्या भी छोटे व्यापारी के लिए गंभीर हो सकती है। RBI के सर्वेक्षण में डिजिटल भुगतान में कठिनाई अनुभव करने वाले उपभोक्ताओं में सर्वर बंद होना या काम न करना सबसे प्रमुख समस्या थी। इसके अतिरिक्त डिजिटल साक्षरता, स्थानीय भाषा की कमी, वृद्ध नागरिकों की तकनीकी कठिनाइयाँ, महिलाओं के पास स्वतंत्र मोबाइल की अनुपलब्धता और शिकायत निवारण की जानकारी का अभाव भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

15. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में UPI को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय

ग्रामीण डिजिटल भुगतान की अगली अवस्था केवल लेन-देन की संख्या बढ़ाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुरक्षित और उपयोगी डिजिटल वित्तीय समावेशन होना चाहिए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय और साइबर साक्षरता कार्यक्रमों को नियमित बनाना आवश्यक है। प्रशिक्षण में केवल UPI चलाना ही नहीं, बल्कि UPI PIN की सुरक्षा, धोखाधड़ी पहचानना, भुगतान विफल होने पर शिकायत करना और गलत खाते में भुगतान होने पर तत्काल कार्रवाई जैसे व्यावहारिक विषय शामिल होने चाहिए।

कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में UPI 123PAY, ऑफलाइन भुगतान और फीचर फोन आधारित सेवाओं को मजबूत करना चाहिए। प्रत्येक ग्रामीण हाट, कृषि मंडी, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और स्थानीय सेवा केंद्र को सुरक्षित डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बैंकिंग प्रतिनिधियों का नेटवर्क ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनके प्रशिक्षण, विश्वसनीयता, तकनीकी उपकरण और शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और कम शिक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय भाषा तथा आवाज आधारित इंटरफेस का विस्तार आवश्यक है। डिजिटल भुगतान के साथ डिजिटल ऋण की सुविधा बढ़ने पर जिम्मेदार ऋण व्यवस्था और डेटा संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक होंगे। RBI ने मार्च 2026 तक Expanding and Deepening of Digital Payments Ecosystem कार्यक्रम के तहत 710 जिलों में 100 प्रतिशत निर्धारित कवरेज प्राप्त होने की सूचना दी है और 2026-27 में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुँच और गहरी करने को प्राथमिकता दी है।

16. निष्कर्ष

डिजिटल भुगतान और UPI भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन का माध्यम बन चुके हैं। UPI की वास्तविक शक्ति केवल इस बात में नहीं है कि इससे भुगतान कुछ सेकंड में हो जाता है, बल्कि इस तथ्य में है कि इसने छोटे मूल्य के आर्थिक लेन-देन को औपचारिक डिजिटल वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना संभव बनाया है। जन-धन खाते, आधार, मोबाइल फोन, बैंकिंग प्रतिनिधि, QR भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने मिलकर ग्रामीण वित्तीय समावेशन का नया ढाँचा विकसित किया है। छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार करने वाले लोगों के लिए डिजिटल भुगतान ने लेन-देन लागत कम की है और व्यापार का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की संभावना पैदा की है। ग्रामीण परिवारों के लिए तत्काल धन हस्तांतरण आर्थिक संकट के समय

सहायता उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। सरकारी योजनाओं में डिजिटल भुगतान ने लाभ हस्तांतरण को अधिक प्रत्यक्ष और पारदर्शी बनाया है। भारत संबंधी अनुभवजन्य अध्ययनों से यह भी संकेत मिलता है कि डिजिटल भुगतान का प्रभाव छोटे व्यवसायों की आय, स्वरोजगार, औपचारिक ऋण तक पहुँच और प्रतिकूल आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता पर सकारात्मक हो सकता है। इसलिए UPI को केवल नकद भुगतान के विकल्प के रूप में देखना इसके आर्थिक महत्व को कम करके आँकना होगा। फिर भी नकद का महत्व निकट भविष्य में पूरी तरह समाप्त होने वाला नहीं है। ग्रामीण भारत में डिजिटल और नकद व्यवस्था का सह-अस्तित्व बना रहेगा। नीति का उद्देश्य नकद समाप्त करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, सस्ता, सरल और विश्वसनीय भुगतान विकल्प उपलब्ध कराना होना चाहिए। यदि डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा, महिलाओं की डिजिटल पहुँच, स्थानीय भाषा आधारित सेवाएँ और प्रभावी शिकायत निवारण साथ-साथ मजबूत किए जाते हैं, तो UPI ग्रामीण अर्थव्यवस्था में केवल भुगतान सुविधा नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, ग्रामीण उद्यमिता, पारदर्शिता और समावेशी आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ

1. भारतीय रिज़र्व बैंक। (2026)। वार्षिक रिपोर्ट 2025-26: भुगतान और निपटान प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी। मुंबई: RBI।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक। (2026)। वार्षिक रिपोर्ट 2025-26: ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन। मुंबई: RBI।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक। (2024)। भारत में डिजिटल भुगतान: विकास और प्रभाव। RBI प्रकाशन।
4. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया। (2026)। UPI उत्पाद आँकड़े। NPCI।
5. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया। (2026)। UPI लाइट। NPCI।
6. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया। (2025)। UPI 123PAY: फ़ीचर फ़ोन को सशक्त बनाना। NPCI।
7. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय। (2026)। प्रधानमंत्री जन-धन योजना प्रगति रिपोर्ट। भारत सरकार।
8. भारत सरकार। (2026)। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) भारत डैशबोर्ड। DBT मिशन।
9. भारत सरकार। (2025)। DBT और अन्य शासन सुधारों से अनुमानित लाभ। DBT मिशन।
10. विश्व बैंक। (2022)। ग्लोबल फ़िडेक्स डेटाबेस 2021: वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और COVID-19 के दौर में लचीलापन। वाशिंगटन, DC: विश्व बैंक।
11. एगुइलर, ए., फ़ॉस्ट, जे., गुएरा, आर., कामिन, एस., और टोम्बिनी, ए. (2024)। डिजिटल भुगतान, अनौपचारिकता और आर्थिक विकास। BIS वर्किंग पेपर्स संख्या 1196। बैंक ऑफ़ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स।
12. पटनम, एम., और याओ, डब्ल्यू. (2020)। मोबाइल मनी के वास्तविक प्रभाव: बड़े पैमाने पर फ़िनटेक विस्तार से प्रमाण। IMF वर्किंग पेपर संख्या 2020/138। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
13. दुबे, टी. एस., और पूर्णानंदम, ए. (2023)। क्या कैशलेस भुगतान आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं? मिशिगन विश्वविद्यालय वर्किंग पेपर।
14. भारतीय रिज़र्व बैंक। (2025)। RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। मुंबई: RBI।
15. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया। (2026)। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस इकोसिस्टम और प्रोडक्ट के आँकड़े। NPCI।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.